

प्रेषक:

नागेन्द्र कुमार प्रसाद  
डी-303, नीलकण्ठ रेसिडेन्सी,  
नियर न्यू एल. पी. श्वानी स्कूल रोड,  
केनाल रोड, पालनपूर, सूरत-395009,  
ई-मेल आडी-112527nag@gmail.com

सेवा में,  
केन्द्रीय नागरिक सूचना अधिकारी,  
शहरी विकाश मंत्रालय,  
नई दिल्ली।

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत केन्द्रीय 'सातवें वेतन आयोग के रिपोर्ट' से संबंधी सूचना हेतु।

महोदय,

मेरा नाम नागेन्द्र कुमार प्रसाद है। मैं केन्द्रीय सातवें वेतन आयोग के लागू किये गये रिपोर्ट के संबंध में कुछ जानकारी चाहता हूँ।

अतः सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत मैं जानना चाहता हूँ कि

- 1- सातवें वेतन आयोग के रिपोर्ट में गृह निर्माण अग्रिम ऋण ट्रांसफर के संबंध में जनना चहता हूँ कि कोई 'सी' वर्ग का सरकारी कर्मचारी निजि बैंक द्वारा 25 लाख गृह निर्माण ऋण लिया है, वर्तमान में रूपये 23 लाख बकाया है। तो:-
  - सरकारी कर्मचारी के सातवें वेतन मैट्रिक्स के अनुसार बेसिक वेतन रूपये 40,000/- है। तो वह कार्यालय से कितने राशि का स्थानांतरण (Transfer) निजि बैंक को किया जा सकता है?
  - यदि पति एवं पत्नी दोनो अलग-अलग सरकारी कार्यालय के कर्मचारी है। जिसमें पति सातवें वेतन मैट्रिक्स के अनुसार बेसिक वेतन रूपये 40,000/- है एवं पत्नी सातवें वेतन मैट्रिक्स के अनुसार बेसिक वेतन रूपये 30,000/- है, तो उपरोक्त वर्तमान में रूपये 23 लाख बकाया मे संयुक्त रूप से या किसके कार्यालय से कितने राशि का स्थानांतरण (Transfer) निजि बैंक को किया जा सकता है?
- 2- क्रम संख्या 1 के संबंध में नियमों पूर्ण विवरण दें, जिससे कर्मचारी सरकारी कार्यालय से गृह निर्माण अग्रिम का लाभ प्राप्त कर सके। (उपरोक्त विवरण दिनांक 25.07.2016 सातवें वेतन आयोग के सिफारिश के रिपोर्ट एवं क्रम सं 11-1/2016-IC दिनांक 06.07.2017 के केन्द्रीय वेतन आयोग के संस्तुत भत्तों में विवरण उपलब्ध नही होने के कारण मांगी गई है।)

3- सरकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के अधिकतम गृह निर्माण अग्रिम ऋण के ब्याज दर (Intrest Rate) वर्ष 2003 से 9.5% है। वर्ष 2003 के बाद वर्तमान समय तक गृह निर्माण अग्रिम ब्याज दर (Intrest Rate) में कोई बदलाव क्यों नहीं किया गया? गृह निर्माण अग्रिम ऋण के ब्याज दर (Intrest Rate) निर्धारित करने नियमों का विवरण बताया जाए।

महोदय वर्ष 2003 के बाद सरकारी एवं निजी बैंकों में गृह निर्माण अग्रिम ऋण के ब्याज दर (Intrest Rate) में काफी परिवर्तन हुआ है। जो वर्तमान में 7 से 8 प्रतिशत के बीच है। सरकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के गृह निर्माण अग्रिम ऋण के ब्याज दर (Intrest Rate) में भी उपरोक्त अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता है।

भवदीय,



नागेन्द्र कुमार प्रसाद